

# वक़्फ संशोधन के तहत संपत्तियाँ पूँजीपतियों को सौंपने की साज़िरा-डॉ. कासिम रखूल इलियास

## संविधान विरोधी क़ानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा

औरंगाबाद, २८ अप्रैल (प्रतिनिधि): सत्ताधारी दल ने अपनी संख्या बल का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और न्यायप्रिय नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध वक़्फ अधिनियम में मनमानी और भेदभावपूर्ण संशोधन पारित कर दिए हैं। हम इन संशोधनों को पूरी तरह से खारिज करते हैं क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के संवेधानिक और मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह बात आल इंडिया मुस्लिम परसनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. कासिम रखूल इलियास ने आज एक पत्रकार वार्ता में कही।

डॉ. इलियास ने कहा कि इन संशोधनों के माध्यम से मुसलमानों को अपनी धार्मिक संपत्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने से रोका गया है। भारतीय संविधान करने से अनुच्छेद २५ और २६ और अपने धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धार्मिक व कल्याणकारी संस्थान स्थापित करने तथा उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। नया कानून इन मूलभूत अधिकारों का खुला उल्लंघन करता है।

डॉ. इलियास ने आगे कहा कि केंद्रीय वक़्फ परिषद और राज्य वक़्फ बोर्डों के सदस्यों के चुनाव से संबंधित संशोधन सकार की दुर्भावना को उजागर करते हैं। वक़्फदाता (वाक़िफ़) के लिए



पाँच वर्षों तक मुसलमान रहने की शर्त संविधान के अनुच्छेद १५ और २६ तथा इस्लामी शरीयत दोनों के विरुद्ध है। ये संशोधन पूरी तरह भेदभावपूर्ण हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करते हैं।

जहाँ विद्वा॒ सिख, इस्लामी, जैन और बौद्ध धर्मों की धार्मिक संपत्तियों को

के लगभग पाँच करोड़ मुसलमानों ने इमेल के माध्यम से अपनी असहमति दर्ज कराई थी, लेकिन संसदीय और लोकतांत्रिक परंपराओं की अवहेलना करते हुए उन अपत्तियों को नजरअंदाज़ कर दिया गया। डॉ. इलियास ने कहा कि अब इन संशोधनों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है और जनता की अदालत में भी न्याय की गुहर लगाई जा रही है। आॅल इंडिया मुस्लिम परसनल लॉ बोर्ड ने इस उद्देश्य के लिए तीन महीने का विस्तृत और शांतिपूर्ण अंदोलन का कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे पूर्ण निष्ठा और संकल्प के साथ लागू किया जाएगा।

आज राज्य संसदीय समिति ने पूरे

महाराष्ट्र में आंदोलन के कार्यक्रम तय किए हैं। राज्य के सभी अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थान, राजनीतिक और सामाजिक नेता इस आंदोलन में सम्मिलित रहेंगे। पूरा कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और संविधान व कानून के दायरे में रहेगा।

इस पत्रकार वार्ता में डॉ. कासिम रखूल इलियास के अलावा बोर्ड के सचिव मौलाना फ़ज़लुर्रहमान मजीदी, बोर्ड के सदस्य मौलाना इलियास खान फ़लाही, मौलाना मोहम्मद शरीफ़ निज़ामी, मोहम्मद हुसैन रजा, कॉर्पोरेड अभ्यर्थी टाक़ा सालू सहित अनेक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नेता उपस्थित रहेंगे।

## पहलगाम आतंकी हमले के बाद बांग्लादेशियों की आड़ में मुसलमानों पर हो रहा अत्याचार बंद किया जाए- अबू आसिम आज़मी

### मुसलमानों को निशाना बनाए जाने और नितेश राणे की भड़काऊ गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग

मुंबई, २८ अप्रैल (अज़ज़ी एजाज़ी):

पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में नफरत का माहौल तेज़ी से फैल रहा है। बांग्लादेशियों के नाम पर मुसलमानों को हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है। राज्य सरकार में मंत्री नितेश राणे लगातार मुसलमानों के खिलाफ ज़हर उगल रहे हैं। संविधान की शपथ लेने के बावजूद वे नफरत का माहौल बना रहे हैं। मुसलमानों पर हो रही हिंसा को रोकने की मांग को लेकर आज अबू आसिम आज़मी ने राज्यभवन में राज्यपाल रेपोर्ट बैस से मुलाकात की और तकाल हस्तक्षेप की मांग की।

अबू आसिम आज़मी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की साजिश खुलकर सामने आ रही है। कुछ नफरती तत्व इस माहौल को और अधिक भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दार्द में बांग्लादेशियों के नाम पर मुसलमानों पर हमला किया गया, साथी जांचियों और रेहड़ी-पटरी वालों को भी हिंसा का शिकार बनाया गया। उन्होंने



अबू आसिम आज़मी ने कहा कि पहलगाम हमले में धर्म पूर्णकर्ता निर्दोषों की हत्या की गई, लेकिन वहीं कश्मीरियों ने पीढ़ित पर्टकों की मदद की। कश्मीरी युवक सेयद हुसैन ने अपनी जान की बाज़ी लगाकर भारतीय पर्यटकों की रक्षा की और कश्मीरियों ने संकट में फ़से पर्यटकों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। इसके बिपरीत, मंत्री नितेश राणे अवलोकन करने से अवश्यकता की बाबत एक ज्ञापन भी दिया।

हैं।

इन्हाँने ही नहीं, नितेश राणे ने हिंदुओं से अपील की है कि वे केवल हुमान चालीसा का पाठ करने वाले दुकानदारों से ही खरीदारी करें और सामान खरीदने से पहले दुकानदार से हुमान चालीसा का पाठ करवाएं। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि मंत्री पद पर रहते हुए नितेश राणे का यह व्यवहार असर्वैधानिक है, इसलिए उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। अबू आसिम ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़ण्डालीस से भी शिकायत की गई थी, लेकिन राज्य में नफरत का माहौल अब भी जारी है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि इस संकट में फ़से पर्यटकों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। इसी कारण अब उन्होंने राज्यपाल से तकाल हस्तक्षेप करने की मांग की है। अबू आसिम आज़मी ने राज्यपाल को इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा।

## मुंबई में १ मई से 'वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट' ; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन

(रिपोर्ट: जमीर काज़ी)

मुंबई, प्रतिनिधि:

मुंबई के बीकैसी स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में १ से ४ मई तक 'वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट' का आयोजन किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन १ मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाथों से होगा।

इस बात की जानकारी उद्योग मंत्री उदय राणे ने सोमवार को बीकैसी में आयोजित एक पत्रकार परिषद के लिए दी। इस समिट की मेजबानी महाराष्ट्र सरकार कर रही है और आयोजन नरेंद्र मोदी देवेंद्र फ़ण्डालीस के नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी १ मई को पूरे दिन मुंबई में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैश्वान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अबू आसिम आज़मी ने राज्यपाल को इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा।

मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है और खास तौर पर हिंदी फ़िल्म उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारतीय फ़िल्म उद्योग के जनक दादासाहेब फ़ालके ने महाराष्ट्र में मराठी सिनेमा की शुरूआत की थी।

इसलिए मनोरंजन के क्षेत्र में मुंबई देश का अग्रणी शहर है। साथ ही, पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र विदेशी निवेश के माले में भी पहले स्थान पर रह है। पर्यटन के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इसी दृष्टि से इस समिट का उद्घाटन की सांस्कृतिक, औद्योगिक और पर्यटन परामर्शदारों द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।

कलाकार व निर्माता भी इस समिट में सामिल होंगे। चार दिवसीय इस आयोजन में भारत, महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि विविध विदेशी निवेशकों द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।

कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित परिसंचाव, रांडू टेबल कांफ्रेंस और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। विशेष आकर्षण के रूप में ३ मई को नवी मुंबई के डी. वाई. पाटिल स्टेडियम में प्रसिद्ध संगीतकार ए. आर. हमान का भव्य सांगीतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

तस्वीर नामा एकजुटता

देश कि हो बात तो चबून है हम। एकजुटता कि भी पहेलान है हम। पुरे न होंगे कभी ना पाक इरादे। वतन के सद्ये मुसलमान है हम।



काजी मखदूम



# १५ अगस्त तक सरकार की सभी सेवाएं ऑनलाइन करें-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

(तामीर काजी)

मुंबई, प्रतिनिधि :

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम को अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए ठास प्रयास किए जाएं। १५ अगस्त २०२५ तक राज्य सरकार की सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। जो विभाग अपनी सेवाओं को तय समय तक ऑनलाइन नहीं करेगा, उस विभाग से प्रतिदिन प्रत्येक सेवा के लिए १००० रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया।

सह्याद्री अतिथिगृह में सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय नवाचार, उत्कृष्टता व सुशासन) और महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग के सुयुक्त तत्वावधान में महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ की

दशकपूर्वी एवं प्रथम सेवा हक्क दिवस के अवसर पर राज्यस्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री फडणवीस संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सचिव ग्रौटोगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोग के मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, आयोग के नव-नियुक्त ब्रांड एंबेसडर पद्माश्री शंकर महादेव, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, पूर्व राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय, कोकण के आयुक्त बलदेव सिंह, पुणे के आयुक्त दिलीप शिंदे सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम के तहत



फिलहाल १००० से अधिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से लगभग ५८३ सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। शेष ३०६ सेवाओं को भी ऑनलाइन लाना बाकी है, जबकि १२५ सेवाएं ऑनलाइन होते हुए,

भी कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें निर्देश दिया कि सभी विभाग १५ अगस्त २०२५ तक अपनी समस्त सेवाओं को ऑनलाइन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान में जो

मौलिक अधिकार शामिल किए, वे सभी नागरिकों को सुनिश्चित रूप से मिलें, यह जरूरी है। पिछले १० वर्षों में तकनीकी क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई है और इसी के अनुरूप सेवाओं को अधिक तीव्र गति से नागरिकों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय में शुरू किए गए फेस वेरिफिकेशन ऐप के कारण भीड़ में काफी कमी आई है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों के जीवन में 'ईंज ऑफ लिविंग' लाना है। यदि सभी सेवाएं व्हाट्सएप और सरकारी बेबाइट्स पर उपलब्ध हो जाएंगी तो नागरिकों की शिकायतें भी काफी हद तक कम होंगी और जीवन स्तर बेहतर होगा।

उपमुख्यमंत्री एकत्र शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र में जनता के

लिए कर्तव्य भावना से कार्य करना चाहिए।

लोकसेवा केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक महान भावना है। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने कहा कि सरकार अत्याधिकारिक तरीका का उपयोग कर नागरिकों को अनुरूप सेवाओं को अधिक तीव्र गति से नागरिकों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रालय में शुरू किए गए फेस वेरिफिकेशन ऐप के कारण भीड़ में काफी कमी आई है।

सरकार का जीवन में 'ईंज ऑफ लिविंग' लाना है।

यदि सभी सेवाएं व्हाट्सएप और सरकारी बेबाइट्स पर उपलब्ध हो जाएंगी तो नागरिकों की शिकायतें भी काफी हद तक कम होंगी और जीवन स्तर बेहतर होगा।

उपमुख्यमंत्री एकत्र शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र में जनता के

लिए कर्तव्य भावना से कार्य करना चाहिए।

लोकसेवा केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक महान भावना है। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने कहा कि सरकार अत्याधिकारिक तरीका का उपयोग कर नागरिकों को अनुरूप सेवाओं को अधिक तीव्र गति से नागरिकों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रालय में शुरू किए गए फेस वेरिफिकेशन ऐप के कारण भीड़ में काफी कमी आई है।

सरकार का जीवन में 'ईंज ऑफ लिविंग' लाना है।

यदि सभी सेवाएं व्हाट्सएप और सरकारी बेबाइट्स पर उपलब्ध हो जाएंगी तो नागरिकों की शिकायतें भी काफी हद तक कम होंगी और जीवन स्तर बेहतर होगा।

उपमुख्यमंत्री एकत्र शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र में जनता के

लिए कर्तव्य भावना से कार्य करना चाहिए।

लोकसेवा केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक महान भावना है। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने कहा कि सरकार अत्याधिकारिक तरीका का उपयोग कर नागरिकों को अनुरूप सेवाओं को अधिक तीव्र गति से नागरिकों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रालय में शुरू किए गए फेस वेरिफिकेशन ऐप के कारण भीड़ में काफी कमी आई है।

सरकार का जीवन में 'ईंज ऑफ लिविंग' लाना है।

यदि सभी सेवाएं व्हाट्सएप और सरकारी बेबाइट्स पर उपलब्ध हो जाएंगी तो नागरिकों की शिकायतें भी काफी हद तक कम होंगी और जीवन स्तर बेहतर होगा।

उपमुख्यमंत्री एकत्र शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र में जनता के

लिए कर्तव्य भावना से कार्य करना चाहिए।

लोकसेवा केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक महान भावना है। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने कहा कि सरकार अत्याधिकारिक तरीका का उपयोग कर नागरिकों को अनुरूप सेवाओं को अधिक तीव्र गति से नागरिकों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रालय में शुरू किए गए फेस वेरिफिकेशन ऐप के कारण भीड़ में काफी कमी आई है।

सरकार का जीवन में 'ईंज ऑफ लिविंग' लाना है।

यदि सभी सेवाएं व्हाट्सएप और सरकारी बेबाइट्स पर उपलब्ध हो जाएंगी तो नागरिकों की शिकायतें भी काफी हद तक कम होंगी और जीवन स्तर बेहतर होगा।

उपमुख्यमंत्री एकत्र शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र में जनता के

लिए कर्तव्य भावना से कार्य करना चाहिए।

लोकसेवा केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक महान भावना है। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने कहा कि सरकार अत्याधिकारिक तरीका का उपयोग कर नागरिकों को अनुरूप सेवाओं को अधिक तीव्र गति से नागरिकों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रालय में शुरू किए गए फेस वेरिफिकेशन ऐप के कारण भीड़ में काफी कमी आई है।

सरकार का जीवन में 'ईंज ऑफ लिविंग' लाना है।

यदि सभी सेवाएं व्हाट्सएप और सरकारी बेबाइट्स पर उपलब्ध हो जाएंगी तो नागरिकों की शिकायतें भी काफी हद तक कम होंगी और जीवन स्तर बेहतर होगा।

उपमुख्यमंत्री एकत्र शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र में जनता के

लिए कर्तव्य भावना से कार्य करना चाहिए।

लोकसेवा केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक महान भावना है। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने कहा कि सरकार अत्याधिकारिक तरीका का उपयोग कर नागरिकों को अनुरूप सेवाओं को अधिक तीव्र गति से नागरिकों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रालय में शुरू किए गए फेस वेरिफिकेशन ऐप के कारण भीड़ में काफी कमी आई है।

सरकार का जीवन में 'ईंज ऑफ लिविंग' लाना है।

यदि सभी सेवाएं व्हाट्सएप और सरकारी बेबाइट्स पर उपलब्ध हो जाएंगी तो नागरिकों की शिकायतें भी काफी हद तक कम होंगी और जीवन स्तर बेहतर होगा।

उपमुख्यमंत्री एकत्र शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र में जनता के

लिए कर्तव्य भावना से कार्य करना चाहिए।

लोकसेवा केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक महान भावना है। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने कहा कि सरकार अत्याधिकारिक तरीका का उपयोग कर नागरिकों को अनुरूप सेवाओं को अधिक तीव्र गति से नागरिकों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रालय में शुरू किए गए फेस वेरिफिकेशन ऐप के कारण भीड़ में काफी कमी आई है।

सरकार का जीवन में 'ईंज ऑफ लिविंग' लाना है।

यदि सभी सेवाएं व्हाट्सएप और सरकारी बेबाइट्स पर उपलब्ध हो जाएंगी तो नागरिकों की शिकायतें भी काफी हद तक कम होंगी और जीवन स्तर बेहतर होगा।

उपमुख्यमंत्री एकत्र शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र में जनता के